



अध्यादेशों का प्रख्यापन और पुनः प्रख्यापन

प्रलिस के लयि:

[अध्यादेश, संसद, राज्यपाल, बैंकिंग कंपनयिों \(उपकरमों का अधगिरहण और हसतांतरण\) अध्यादेश, 1969](#), नयायकि समीक्षा, आर.सी. कूपर बनाम भारत संघ (1970)

मेन्स के लयि:

भारत में अध्यादेशों का अधनियमन, अध्यादेश का पुनः प्रख्यापन

चर्चा में कयों?

हाल ही में भारत के राष्ट्रपतिने **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (National Capital Territory- NCT)** में [दिल्ली के उपराज्यपाल](#) को सेवाओं के संदर्भ में अधिकार देते हुए [अध्यादेश](#) जारी या प्रख्यापति कयिा है ।

- इस अध्यादेश के तहत "राष्ट्रीय राजधानी सविलि सेवा प्राधकिरण" की स्थापना की गई जसिमें [मुख्यमंत्री](#) और दो वरषिठ IAS अधिकारी शामिल हैं, जो उन्हें बहुमत के माध्यम से मामलों को तय करने का अधिकार प्रदान करता है ।
- आलोचकों का तर्क है कयिह कदम प्रभावी रूप से ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है जहाँ नरिवाचति मुख्यमंत्री के वचिरों को संभावति रूप से खारजि कयिा जा सकता है ।

भारतीय राजनीति में अध्यादेश:

परचिय:

- भारत के संवधिान का अनुच्छेद 123 जब [संसद](#) के दोनों सदनों में से कोई भी अत्यावश्यक परस्थितियिों में सत्र में नहीं होता है तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने हेतु कानून बनाने की कुछ शक्तियिों प्रदान करता है ।
 - इसलिये संसद द्वारा अध्यादेश जारी करना संभव नहीं है ।
 - जब अध्यादेश प्रख्यापति कयिा जाता है लेकनि वधायी सत्र अभी शुरू नहीं हुआ है, तो अध्यादेश कानून के रूप में प्रभावी रहता है । इसकी वही शक्ति एवं प्रभाव है जो वधायिका के अधनियम का होता है ।
 - लेकनि इसके पुनः प्रख्यापन के छह सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक होता है ।
 - राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापति अध्यादेश की वैधता इसके प्रख्यापन की तारीख से छह सप्ताह और अधिकतम छह महीने तक होती है ।
- कसिी राज्य का [राज्यपाल](#) भी राज्य में वधिानसभा सत्र न होने की स्थितिमें भारत के संवधिान के अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है ।
- यददोनों सदन अलग-अलग तथियिों पर अपना सत्र शुरू करते हैं, तो बाद की तारीख पर वचिर कयिा जाता है(अनुच्छेद 123 और 213) ।

अधनियमन:

- अध्यादेश बनाने की प्रक्रिया में अध्यादेश लाने का नरिणय सरकार के पास होता है, कयोंकि [राष्ट्रपति मंत्रपरिषद](#) की सलाह पर कार्य करता है ।
 - यदद राष्ट्रपति आवश्यक समझे, तो वह मंत्रमिंडल की सफिरशि के लयि पुनर्वचिर हेतु इसे वापस कर सकता है ।
 - हालाँकि यदद इसे वापस (पुनर्वचिर के साथ या बनिा) भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति को इसे प्रख्यापति करना होता है ।

अध्यादेश की वापसी:

- कसिी संभावति कमी के कारण राष्ट्रपति एक अध्यादेश को वापस ले सकता है और संसद के दोनों सदन इसे असवीकार करने के लयि संकल्प पारति कर सकते हैं । हालाँकि एक अध्यादेश की असवीकृति का अर्थ यह होगा कसि सरकार ने बहुमत खो दयिा है ।
 - हालाँकि यदद कोई अध्यादेश संसद की क्षमता के दायरे से बाहर कानून बनाता है, तो इसे शून्य माना जाता है ।

अध्यादेश का पुनः प्रख्यापन:

- जब कोई अध्यादेश समाप्त हो जाता है, तो सरकार आवश्यकता पड़ने पर इसे फरि से प्रख्यापति करने का वकिलप चुन सकती है ।

- वर्ष 2017 के एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कविधायी वचिार के बनिा बार-बार पुनः प्रचार करना असंवैधानकि होगा और वधियकि की भूमकिा का उल्लंघन होगा ।
 - न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति को एक आपातकालीन उपाय के रूप में माना जाना चाहिये, न कि वधियकिा को बायपास करने के साधन के रूप में ।

नोट: कसिी भी अन्य कानून की तरह एक अध्यादेश पूर्वव्यापी हो सकता है यानी यह पछिली तारीख से लागू हो सकता है । यह संसद के कसिी अधनियिम या कसिी अन्य अध्यादेश को संशोधति या नरिसत् भी कर सकता है ।

फायदा	नुकसान
वे जरूरी मामलों पर त्वरति और प्रभावी कार्रवाई की अनुमति देते हैं ।	वे कानून बनाने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दरकिनार करते हैं और संसदीय नरिीक्षण को कम करते हैं ।
वे वधियी बाधाओं के बनिा नीति कार्यान्वयन को सक्षम करते हैं ।	वे शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को कमज़ोर करते हैं और वधियकिा के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं ।
न्यायकि अंतर या असपष्टता के मामले में वे कानूनी नश्चितता और सपष्टता प्रदान करते हैं ।	वे कानूनी अस्थिरता पैदा करते हैं क्योंकि वे अस्थायी हैं और परिवर्तन या नरिसन के अधीन हैं ।
वे कार्यकारी शाखा की अनुकरयिता और जवाबदेही को दर्शाते हैं ।	उनका राजनीतिक या व्यक्तिगत लाभ के लिये या सार्वजनिक जाँच या बहस से बचने हेतु दुरुपयोग किया जा सकता है ।

अध्यादेशों पर अन्य वगित न्यायकि घोषणाएँ:

- **आर.सी. कूपर बनाम भारत संघ (1970):** इस मामले ने **बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधगिरहण और हसतांतरण) अध्यादेश, 1969** को चुनौती दी, जसिने भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया ।
 - सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, अध्यादेश की आवश्यकता के संबंध में राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायकि समीक्षा से मुक्त नहीं है और इसे चुनौती दी जा सकती है ।
 - न्यायालय के अनुसार, एक अध्यादेश संसद के अधनियिम के समान संवैधानकि सीमाओं के अधीन है और संवधान के कसिी भी मौलिक अधिकार या अन्य प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर सकता है ।
- **ए.के. राय बनाम भारत संघ (1982):** इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश, 1980 को चुनौती दी गई थी, जसिमें बनिा मुकदमे के एक वर्ष तक के लिये व्यक्ति को नवारिक हरिसत् में रखने का प्रावधान था ।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने अध्यादेश की वैधता का समर्थन किया, लेकिन इसके संचालन के लिये कुछ सुरक्षा उपाय नरिधारति किये जैसे कि एक सलाहकार बोर्ड द्वारा समय-समय पर समीक्षा, हरिसत् में लिये गए व्यक्ति को हरिसत् के आधार की सूचना देना और हरिसत् के खिलाफ प्रतनिधितिव का अवसर देना ।
 - न्यायालय के अनुसार, एक अध्यादेश का उपयोग संसदीय कानून के विकल्प के रूप में नहीं किया जाना चाहिये और इसका उपयोग केवल अत्यावश्यकता या अप्रत्याशति आपात स्थिति के मामलों में किया जाना चाहिये ।
- **डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य (1987):** इस मामले ने वभिनि वषियों पर वर्ष 1967-1981 के बीच बिहार के राज्यपाल द्वारा जारी किये गए अध्यादेशों की एक शृंखला को चुनौती दी, जनिमें से कुछ को वधिानसभा द्वारा पारति किये बनिा कई बार प्रख्यापति किया गया था ।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने सभी अध्यादेशों को असंवैधानकि बताते हुए रद्द कर दिया तथा यह माना कि अध्यादेशों का पुनः प्रख्यापन संवधान के साथ धोखा और लोकतांत्रिक वधियी प्रक्रिया का उल्लंघन है ।
 - न्यायालय ने यह भी कहा कि एक अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाता है यदि इसे वधियकिा द्वारा पुनः इसके सत्र के छह सप्ताह की अवधि में अनुमोदति नहीं किया जाता है और पुनः प्रख्यापन द्वारा इसे जारी नहीं रखा जा सकता है ।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस